>

Title: Regarding Criteria to be adopted for caste-based census in the ongoing census in the country.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रणब बाबू से बात हुई थी। हमने साफ-साफ कहा था कि अकेले कास्ट का इन्यूमेरेशन हमने कभी नहीं मांगा था। हम चाहते हैं कि जनगणना को जाति के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थित को भी जोड़ा जाए। प्रणब बाबू तैयार थे और उन्होंने हमें कहा कि हमें फार्मेट बना कर दीजिए, हम लोग तैयार हैं। गृह मंत्री जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने साफ-साफ नहीं कहा।

मेरी विनती है कि अकेले जाति का इन्यूमेरेशन करने से काम नहीं चलेगा, यह सिर्फ चुनाव के काम आएगा। देश के अंदर जो सामाजिक, आर्थिक विषमता का पता लगाना है, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। आप जाति के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को भी जोड़िए, यही हमारी मांग है। प्रणब बाबू इसके लिए एग्री थे।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल संक्षेप में सुझाव दीजिएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। यह प्रचार हो रहा है कि हम त्रिगुटी यह सब करवा रहे हैं। क्या हम यादवों के लिए मांग रहे हैं? हम ऊंची जातियों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए मांग रहे हैं। हमारी राय यह है कि केवल जाति लिखने से काम नहीं चलेगा, उसमें उनकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी लिखने की आवश्यकता है। इसी से पता चलेगा कि उनकी क्या स्थिति है? उसमें जब जाति की, शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति लिखी जाएगी, तब उनकी साफ स्थिति आपके सामने आएगी। इसके बाद उन्हें विशेष दर्जा देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। देश के अंदर गैर बराबरी के कारण नफरत है, असमानता है, वैमनस्य है, दुश्मनी है। इसकी वजह से दूरियां बढ़ रही हैं। जातियों में अविश्वास बढ़ रहा है और धर्म के नाम पर भी अविश्वास बढ़ रहा है। मेरी आपके द्वारा गृह मंत्री जी से अपील है कि अपने बयान में संशोधन करके, हम सभी लोग जो कह रहे हैं, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और जाति के आधार पर जनगणना करायी जाए। इसमें आपको आपत्ति क्या है? ऊंची जाति, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई भी गरीब हैं। इससे सबकी स्थिति सामने आ जाएगी। अंततोगत्वा इसका लाभ आपको ही होगा।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1939 के बाद जातिगत आधार पर जनगणना करने की मांग हमने उठायी थी। लेकिन अब जो फार्म बनाया गया है, उसमें हमारी जो मांग थी, उसको शामिल नहीं किया गया है। प्रणब दा ने और प्रधानमंत्री जी ने भी हाउस में घोषणा की थी कि जाति के आधार पर सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस और उनकी परिस्थिति क्या है, की जानकारी ली जाएगी? केवल जाति जानने से कोई लाभ नहीं है। ऊंची जाति में भी पिछड़े लोग हैं। समाज की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। केवल जाति लिखने से कोई फायदा नहीं है। उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति आनी चाहिए, उसके पास क्या कोई जमीन है, घर है, इत्यादि, लेकिन ऐसा कोई कॉलम फार्म में नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सोशल जस्टिस और इकॉनामिक जस्टिस मिले। बहुत सी जातियों में पिछड़े हुए लोग हैं। इसलिए आपको हमारी इस मांग को मान लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सदन के नेता इस पर बयान दें। तीनों यादवों के साथ मैं भी उस मीटिंग में था। उस मीटिंग में जो वादा किया गया था, वह निभाया नहीं है। केवल जाति के आधार पर जनगणना करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर जनगणना नहीं होती, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। मैं मांग करता हूं कि प्रणब दा इस पर बयान दें।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गणेश सिंह, गोपीनाथ मुंडे जी ने जो कहा है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हैं। श्री दारा सिंह चौहान, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें, क्योंकि यह कोई डिबेट नहीं है।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सदन में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। सदन के नेता ने आश्वासन भी दिया था, उन्होंने कल बजट में भी कहा है। लेकिन सच्चाई इससे दूर है। हम सब चाहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना हो, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर भी हो। आज समाज में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है। अगर इसे सरकार देश से खत्म करना चाहती है, तो जैसे मेरी पार्टी का मानना है कि जितनी जिसकी संख्या भारी - उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह होना चाहिए। आज समाज के आधार पर लोग विरोध करते हैं कि जाति के आधार पर क्यों, जब जाति के आधार पर किसी को बड़ा या छोटा माना गया है इसलिए हमारी पार्टी की मांग है कि जाति के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। तब जाकर इन लोगों के साथ इन्साफ हो सकता है और हम देश से गैर बराबरी खत्म कर सकते हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): उपाध्यक्ष जी, जातीय आधार पर जनगणना कोई खास बिरादरी और वर्ग की मांग हम लोगों ने नहीं की थी। इस देश में अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी और उसके बाद साजिश के तहत इसे बंद कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि तमाम दलों के लोगों ने और हमने भी यह मांग की है और सरकार की आंख खोलने का काम किया है कि हम अभी तक जो काम कर रहे हैं, वह अंदाजे पर कर रहे हैं। इसलिए सब जातियों की जनगणना हो। अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरियों में जाना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ी है। मैं सरकार को और प्रणब बाबू को धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वीकार किया कि हम जाति के आधार पर जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन उस जनगणना का कोई मतलब नहीं है, जब तक इन लोगों की माली हालत, शैक्षणिक हालत का पता न चले। चाहे वे मुस्लिम हों, अपर कास्ट के हों या क्रीमी लेयर के हों। जाति के साथ उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार को भी शामिल करेंगे तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी। जनगणना फार्म में एक कालम जाति के साथ-साथ उसकी माली हालत, शैक्षणिक हालत और सामाजिक हालत क्या है, इसका भी समावेश होना चाहिए। इस बात पर हमारा ज्यादा जोर है। सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मुलायम सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीएसपी और अन्य सभी दलों की तरफ से जो बात सामने आई है, हम लोग भी आग्रह करते हैं कि आप इसे करें। इससे सारी स्थिति का पता चल जाएगा इसलिए जाति के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत को भी इसमें शामिल किया जाए।

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, historically, the social status of Indian society has come to a stage to be identified by virtue of caste. I do not think the Government will be averse to take such a census during the enumeration itself. So, I request the Government to come forward to take the caste criteria also in this Census. Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basu Deb Acharia; please be brief.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): This is a disparity in the society and there is a gap between the socially, educationally and economically backward sections and those who are advanced sections of society. So, in order to find out as to what is the status of this population, who are socially, economically and educationally backward, जो विषमता है हमारे समाज में, हमारे देश में, वह विषमता बढ़ रही है। यह जो जनगणना हो रही है, इसमें देखना चाहिए कि कितना गैप बढ़ा है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसके लिए जनगणना में यह रिपोर्ट आनी चाहिए।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am also associating with the other Hon'ble Members on this issue. As they have mentioned, when we are taking the Census, details about caste and also about their economic status and education must be included.

Sir, further I would like to ask the Home Minister regarding the telephone tapping issue. He has not yet responded to that. Our Madam's phones are tapped. But the Minister is not responding to that. I would request him to respond to that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sudip Bandyopadhyay.

...(*Interruptions*)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मुझे भी इस मौके पर बोलने का आपको मौका देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें बात आ गयी, सभी का बोलना तो मुश्किल है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, on behalf of the Trinamool Congress Party, we fully support the caste-wise Census which has already been announced by the hon. Pranab Mukherjee in his Budget speech. Also Shri P. Chidambaram has said that the Members would have enough opportunity and scope to deliver their opinion during the discussion on the Budget.

We also would like to urge − it can certainly be taken for granted or for discussion − that financial and social conditions of these sections may also be considered at the time of the Census.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): हमारी पार्टी की तरफ से हमें भी बोलने का मौका देना चाहिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप कुछ बोलना चाहेंगे।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : डिबेट नहीं करनी है, इसमें सबकी राय आ गयी है, आप समर्थन कर दीजीए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेगौडा जी आप बोलिये। श्री देवेगौडा जी के अलावा किसी और का रिकार्ड में नहीं जाएगी। ...(व्यवधान) *

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Hon. Deputy-Speaker, Sir, firstly I would like to express my sincere thanks to the hon. Home Minister. Sir, you have called him and he was prepared to start his reply. In the meantime I intervened and requested you to allow me to speak. The hon. Home Minister obliged and allowed me to speak.

Sir, regarding this caste issue, I would like to sincerely make an appeal to all sections of the society, whether they agree with me or not agree with me. In 1973, when the late Shri D. Devaraj Urs was the Chief Minister in Karnataka, I had moved a Resolution. My Party had hardly got 24 Members at that time. I was the Leader of the Opposition in the Karnataka Assembly. I came to Delhi; I sat in the Central Hall Library; I took all the relevant documents relating to the Backward Class Commission and the Scheduled Caste Commission. I took three years' Reports of Bihar and Uttar Pradesh only. Why I had taken the Reports of these two States is this. I am not going to make or cast aspersion against anybody. Bihar was represented by the late Babu Jagjivan Ram, and Uttar Pradesh was represented by the tallest leader, Pandit Jawaharlal Nehru. I had taken the Reports of these two States and tried to compare as to how these sections developed economically and socially. I had made an ample study on that, and I had moved the Resolution in the Karnataka Assembly.

It was discussed for about 22 non-official days. We were strictly going to follow the non-official days in those days.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may please give your suggestion.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : Just one second, Sir. Why I am going to tell this is that Mr. Devraj Urs had admitted...(*Interruptions*) I know my limitations. I do not want to make any irrelevant speech.

The then hon. Deputy Chief Minsiter, Mr. Devraj Urs had admitted it and appointed Havanur Commission first, which gave a detailed report pertaining to the entire country. He had done a voluminous work. Mandal commission and Havanour Commission had been formed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, please wind up.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : I beg of you. I beg the Government and I sincerely appeal to the Government. In the Scheduled Caste itself, in Karnataka, there is one community called Dori Samaj; and their profession is only skinning the animals....(*Interruptions*) In the Scheduled Castes, there are so many communities. How are they living today? In what condition are they living today? We have all agreed to extend the reservations for the Scheduled Castes. After Independence till now it is there. Mr. Vajapayeeji had extended it for 25 more years.

Today, we need the caste-wise enumeration. I can quote a number of instances even in the Backward Classes. I do not want to take more time of the House. But the caste-wise Census is a must. It is economically, socially and politically necessary. There is no question of any hesitation from my side that it is necessary even politically. All these three aspects must be taken into consideration. There is no question of any compromise on that.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, we are reiterating our demand for a caste based enumeration. Last year, I had put-forth the logic why a caste based enumeration was required. I need not go into all those aspects now. We had demanded, during that period, when census is taking place, only add one more column for this so that we come to know how many numbers of

people are in the respective castes. The caste is a reality in our country. Enumeration of caste is not unconstitutional. That is why different plans and programmes can come up. As it is being done for the Scheudled Castes and the Scheduled Tribes, so also respective plans and programmes can come up. The Planning Commission can also dwell into that matter and accordingly, programmes can be prepared.

That is why this idea is being floated today. I support this idea as to what is the economic status of respective Castes, what is the social status of respective castes and what is the educational position of respective castes. All this should also be enumerated. I would request the Government to look into this matter and take steps accordingly.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): उपाध्यक्ष महोदय, 80 साल के बाद देश में जाति आधारित जनगणना के लिए सरकार ने एग्री किया है। कल बजट भाषण में भी प्रणब मुखर्जी जी ने मेंशन किया था। इस बारे में हाउस में कई बार डिस्कशन भी हुआ है। डिस्कशन में फार्मेट को सबकी राय से फाइनल किया था। जाति आधारित जनगणना के साथ-साथ सोशल, इक्नोमिकल पोजीशन्स भी मेंशन होनी चाहिए। It is required educationally and politically also. ये सभी इश्यु जनगणना में होने चाहिए। इस बारे में बार-बार डिस्कशन नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : इस बारे में बहुत बार डिसकशन हो चुका है। हाऊस स्टाल होने के बाद बुलाते हैं और करेंगे, कहते हैं फिर भी इस तरह से यह हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): मैं एक ही बात कहना चाहता हूं।मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सदन के लोग सेंसेस करने में किसलिए डर रहे हैं? इसमें किसी के ऊपर आंच नहीं आने वाली है। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। मैं सदन के नेता से निवेदन करता हूं कि देश यह जानना चाहता है कि उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। रिजर्वेशन की बात नहीं है, इस देश में किस प्रकार की जातियां हैं, यह जानना हक है और यही हमारी विनती है।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक (बारामुला): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है और बात तो एक ही है, इसमें मज़ीद जोड़ने की जरूरत नहीं है कि वे लोग जो इरतसाजी, मुआशी, समाजी और ताएलीमी तौर से पिछड़े हैं, उनका नाम, जात और स्टेटस लिखा जाए। यह सीधी सी बात है। इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता है। किसी ने नीची जात की बात कही, मैं इस लफ्ज़ को बर्दाश्त नहीं करता हूं। हिन्दुस्तान में नीचा कोई नहीं है, सब जात बराबर हैं। अगर हम नीची जात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम महात्मा गांधी जी की तौहीन कर रहे हैं, हिन्दुस्तान के आईन की तौहीन कर रहे हैं। यहां सब बराबर हैं, नीची जात लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की तरफ से हमें कहा जा रहा है कि जनगणना के दौरान, मरदुमशुमारी के दौरान कुछ लोग डेलीब्रेटली उनकी आबादी को कम दिखाना चाहते हैं। मैं इसके लिए गवर्नमेंट से इल्तजा करूंगा कि इस पर कड़ी नजर रखी जाए। शुक्रिया।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, many, many thanks to you.

I do unequivocally support the issue which has been raised by the Members of different political Parties. जाति के आधार पर जनगणना होनी ही चाहिए। इसके साथ मैं सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में तमाम अनुसूचित जनजाति की आबादी है। But in each and every Census operation done in the recent past, all the Tribal people of this great country, India, were with other different religions. Why the indigenous Tribal people of India those who are still having of their own religions should not be written along with their respective indigenous religions?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): जितनी मंगोलाइड कुल के ट्राइब्स हैं, जितने बौद्ध लोग हैं, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग आज देश में हैं-उन सभी लोगों का आज भी अपना-अपना धर्म है। अतः उन लोगों को अपने-अपने धर्मों के साथ चलते हुए जनगणना में रिकार्ड करने की जरूरत है। जिनके अपने धर्म हैं, धर्मों के साथ सेंसेस ऑपरेशन गणना करने की जरूरत है। All the

Tribal people of India should be written in the Census along with their respective indigenous religion. यह हमारी मांग है, जबरदस्त मांग है। धन्यवाद।

श्री जोसेफ टोप्पो (तेज़पुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे देश में विभिन्न जाति और धर्म हैं और रहेंगे लेकिन इसे जानने के लिए किसे तकलीफ है? कौन सी तकलीफ है? पिछड़े लोगों का स्टेटस पता होना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि आज हाउस एक मत हुआ है, इनकी एजुकेशन, सामाजिक स्थिति इसमें रखनी चाहिए। धन्यवाद। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जीरो आवर।

श्री भूपिन्द्र सिंह।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): गृह मंत्री जवाब दें।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, the Government has carefully listened to the hon. Members. We have got the sense of the House. All the suggestions will be carefully considered and appropriate decisions will be taken. ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भूपेन्द्र सिंह जी, अब आप बोलिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री भूपेन्द्र सिंह : लालू जी, आप बैठिये, जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जितना जीरो ऑवर में बोलना चाहिए, उतना उन्होंने बोल दिया, सरकार की तरफ से जवाब आ गया। श्री भूपेन्द्र सिंह जी, आप बोलिये।

â€¦(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, so far as the caste-based census is concerned, the Home Minister has already responded. While the House was adjourned for the time being, I requested Mr. Sharad Yadav, Mr. Mulayam Singh Yadav and any other who is interested that what ingredients you want to be put in the format for which the caste census will be operated. Kindly prepare it and hand it over to us and we will look into those aspects. So, what is there to debate? The Home Minister has also responded to that.